

प्रमुख सचिव से मिले मर्चेंट चैंबर के सदस्य

कानपुर। मर्चेंट चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को लखनऊ में प्रदेश सरकार के एमएसएमई प्रमुख सचिव आलोक कुमार से मुलाकात की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव को ज्ञापन भी दिया गया। संपत्ति कर छूट, जीएसटी संबंधी चुनौतियां, औद्योगिक लाइसेंसिंग और रक्षा सुविधाओं समेत तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रेम मनोहर गुप्ता, सुशील शर्मा, अनिल शरन गर्ग, रू

लखनऊ जाकर बताई एमएसएमई सेक्टर की समस्याएं

कानपुर (एसएनबी)। मर्चेन्ट्स चैम्बर की इंडस्ट्री समिति के पदाधिकारियों ने लखनऊ जाकर प्रदेश सरकार के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार को एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी समस्याओं के विषय में विस्तार से अवगत कराया। मर्चेंट्स चेम्बर के प्रतिनिधि मंडल से प्रेम मनोहर गुप्ता, एडवाइजर, इंडस्ट्री समिति, अनिल शरन गर्ग, वाईस-चेयरमैन, इंडस्ट्री समिति , रूफी वाकी, वाईस-चेयरमैन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट समिति, महेंद्र मोदी आदि ने संपत्ति कर छूट पर बताया कि सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के तहत, राज्य सरकार ने नगर पालिका एवं नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को संपत्ति कर निर्धारण के संबंध में कुछ छूट दी है। एसएमई के लिए पूरे देश में इससे छूट दी जानी चाहिए। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने एमसीयूपी द्वारा चिंताओं को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

'एमएसएमई इकाई को जमानत मुक्त ऋण नहीं दे रहे बैंक'

जासं, कानपुर : मर्चेंट्स चैंबर आफ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी सोमवार को लखनऊ में एमएसएमई व निर्यात संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार से मिले और शिकायत की कि बैंक एमएसएमई इकाइयों को जमानत मुक्त ऋण नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को इसके लिए निर्देश दिया जाए कि वे जमानत मुक्त ऋण दें। कानपुर में रक्षा सुविधा केंद्र की स्थापना की बात भी कही गई।

उद्यमियों की समस्याएं रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने नगर पालिका एवं नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित एमएसएमई इकाइयों को संपत्ति कर निर्धारण में छूट दी है। नगर निगम क्षेत्राधिकार में भी इसे लागू किया जाए। जेम पोर्टल पर 20 लाख रुपये से अधिक के ऑर्डर के लिए उच्च शुल्क वसूल जा रहा है, इसे माफ किया जाए पदाधिकारियों ने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कानपुर में विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले प्रदर्शन केंद्र की मांग की। सरकारी खरीद में 50 प्रतिशत एडवांस दिलाया जाए भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नियमों के तहत कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 करने के लिए कहा गया। संगठन के उद्योग समिति के सलाहकार प्रेम मनोहर गुप्ता, अध्यक्ष सुशील शर्मा उपाध्यक्ष अनिल शरण गर्ग, आयात निर्यात समिति के अध्यक्ष रूफी वकी, सचिव महेंद्र मोदी आदि रहे।

www.livehindustan.com
हिन्दुस्तान
कानपुर, मंगलवार, 6 अगस्त 2024



प्रमुख सचिव से मिले मर्चेंट चैंबर के सदस्य

कानपुर। मर्चेंट चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को लखनऊ में प्रदेश सरकार के एमएसएमई प्रमुख सचिव आलोक कुमार से मुलाकात की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव को ज्ञापन भी दिया गया। संपत्ति कर छूट, जीएसटी संबंधी चुनौतियां, औद्योगिक लाइसेंसिंग और रक्षा सुविधाओं समेत तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रेम मनोहर गुप्ता, सुशील शर्मा, अनिल शरन गर्ग, रूफी वाकी, महेंद्र मोदी आदि रहे।

उद्यमियों ने प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंप बताईं समस्याएं

कानपुर। मर्चेंट्स चैंबर ऑफ उप्र के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात संवर्धन के प्रमुख सचिव आलोक कुमार को ज्ञापन दिया।

प्रमुख सचिव से संपत्ति कर में छूट, एमएसएमई में कार्यशील पूंजी, जेम पोर्टल से 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सप्लाई ऑर्डर के लिए एसओ अपलोड होते ही उच्च शुल्क वसूले जाने की समस्या बताई। जीएसटी की जटिलता, औद्योगिक लाइसेंसिंग और रक्षा सुविधा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया, ताकि कानपुर-झांसी क्षेत्र में रक्षा गलियारे का दायरा बढ़ाया जा सके। शहर में औद्योगिक प्रदर्शनी केंद्र की स्थापना की मांग उठाई।

परफॉर्मेंस बैंक गारंटी अग्रिम भुगतान, फुटवियर पर भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंड (बीआईएस) आदि से हो रहीं समस्याएं रखी गईं। टूल रूम के बेहतर संचालन और बीआईसी, एनटीसी की जमीनों में औद्योगिक पार्क की स्थापना करवाने की मांग की गई। प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के विकास का समर्थन और प्रचार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस मौके पर प्रेम मनोहर गुप्ता, सुशील शर्मा, अनिल शरन गर्ग, रूफी वाकी, महेंद्र मोदी रहे। (ब्यूरो)

आज
कानपुर, 6 अगस्त 2024 4

एमएसएमई में आ रही समस्याओं पर चर्चा

नगर निगम के तहत सम्पत्ति कर में मिले छूट

कानपुर, 5 अगस्त। सम्पत्ति कर में छूट, जीएसटी की चुनौतियों, औद्योगिक लाइसेंसिंग और रक्षा सुविधा और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी आदि में आ रही परेशानियों को लेकर सोमवार को मर्चेंट्स चैम्बर का प्रतिनिधि मण्डल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी और निर्यात संवर्धन प्रमुख सचिव आलोक कुमार से मुलाकात की। मुलाकात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा सामना की जा रही महत्वपूर्ण समस्याओं और अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गयी। प्रतिनिधि मण्डल ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने नगर पालिका एवं नगर पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सम्पत्ति कर निर्धारण के संबंध में कुछ छूट दी है। इसमें नगर निगम के क्षेत्राधिकार को भी शामिल किया जाये। बैंक किसी भी एमएसएमई को जमानत मुक्त ऋण देने के लिए मंजूरी या समर्थन नहीं दे रहे हैं। जिसपर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जीएसटी पोर्टल 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सप्लाई ऑर्डर के लिए एसओ अपलोड होते ही उच्च शुल्क वसूल रहा है। इसे या तो माफ किया जाना चाहिए या खरीदार से भुगतान प्राप्त होने के समय ही वसूला जाना चाहिए। औद्योगिक लाइसेंसिंग और रक्षा सुविधा के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता है। विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र के लिए। एमएसएमईएस के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी से छूट या एक वैकल्पिक रूप में बीमा रसीदों की स्वीकृति का अनुरोध किया। जिससे वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू और विदेशी खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कानपुर में सभी विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त एक प्रदर्शनी केन्द्र की तत्काल आवश्यकता है। म्यूर मिल, सिविल लाइन्स, कानपुर की बेकार पड़ी जमीन का औद्योगिक भू-उपयोग करते हुए आईटी एवं कारपोरेट पार्क की स्थापना की जाये। मुलाकात करने में प्रेम मनोहर गुप्त, सुशील शर्मा, अनिल शरन गर्ग, रूफी वाकी, महेंद्र मोदी शामिल रहे।



प्रमुख सचिव आलोक कुमार के साथ प्रतिनिधि एमसीयूपी।

● एमसीयूपी के प्रतिनिधि मण्डल ने की एमएसएमई और निर्यात संवर्धन प्रमुख सचिव से मुलाकात